



भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA

यूटीआई UTI

1964-2014

50 years of pioneering wealth creation



विवरणिका BROCHURE



तकनीकी आंकड़े TECHNICAL DATA

जारी करने की तारीख Date of Issue	:	12 नवम्बर, 2014 12 November, 2014
मूल्यवर्ग Denomination	:	500 पैसा 500 p
मुद्रित डाक-टिकटें Stamps Printed	:	40.3 लाख* 4.03 Million*
मुद्रण प्रक्रिया Printing Process	:	वेट ऑफसेट Wet Offset
मुद्रक Printer	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद Security Printing Press, Hyderabad

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास हैं।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

*35.3 लाख प्रस्तावक हेतु।

*3.53 Millions on for the proponent.

मूल्य ₹ 5.00

UTI

The objective of India's development strategy has been to establish a socialistic pattern of society through economic growth with self-reliance, social justice and alleviation of poverty. These objectives were to be achieved within a democratic political framework using the mechanism of a mixed economy where both public and private sectors co-existed. In the 1960s, the era of Green revolution and industrialization, the planners and policy makers suggested the need for using a wide variety of instruments like state allocation of investment, licensing and other regulatory controls to steer Indian industrial development on a closed economy basis. This led to the establishment of the UTI or the Unit Trust of India through the Unit Trust of India Act, 1963 of the Parliament.

UTI was set up by the Reserve Bank of India (RBI) and functioned under its Regulatory and administrative control. It commenced its operations from 1st February, 1964 with the objective of mobilizing savings of the community and providing the small investors with a means of acquiring a stake in the industrial growth of the country. The first scheme launched by UTI was Unit Scheme 64. In 1978, UTI was de-linked from the RBI and the Industrial Development Bank of India (IDBI) took over its regulatory and administrative control.

UTI remained the sole vehicle for investment in the Indian capital market for more than two decades, after which, the public sector banks were allowed to enter the foray. The vibrancy and competition increased with the setting up of the Security Exchange Board of India, a regulatory body. The Unit Trust of India Act, 1963 was repealed in 2001. This was followed by the bifurcation of the organization into - Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI); and UTI Mutual Fund (UTIMF) on 1st February, 2003.

Today, the two branches of UTI are carrying forward the legacy of the parent organization. The Specified

Undertaking of the Unit Trust of India, with assets worth ₹ 29,835 crores at the end of January 2003, represented broadly, the assets of US 64 scheme, assured return and certain other schemes. This is a Specified Undertaking of Unit Trust of India, functioning under an administrator and under the rules framed by Government of India, and does not come under the purview of the Mutual Fund Regulations.

The second branch is the UTI Mutual Fund, sponsored by State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda and Life Insurance Corporation, with each of them holding 18.5% stake in the paid up capital of UTI AMC. It is registered with SEBI and functions under the Mutual Fund Regulations. With the bifurcation of the erstwhile UTI, which had in March, 2000 more than ₹ 76,000 crores of assets under its management, and with the setting up of a UTI Mutual Fund, conforming to the SEBI Mutual Fund Regulations, along with recent mergers taking place among different private sector funds, the mutual fund industry has entered its current phase of consolidation and growth.

UTI is the oldest and one of the largest mutual fund in India. UTI Mutual Fund has been the pioneer for launching various schemes like UTI Unit Linked Insurance Plan (ULIP) with life & accident cover (Launched in 1971). Over the years, brand UTI has taken up the role of wealth creator for the masses. UTI is a process-oriented financial powerhouse with core business principle being customer delight through consistent fund performance and excellent service.

Department of Posts is happy to celebrate the journey of UTI by releasing a Commemorative Postage Stamp on it.

Credits:-

Text	: Based on the text provided by the proponent and the internet.
Stamp/FDC	: Kamleshwar Singh
Cancellation	: Alka Sharma

यूटीआई

भारत में विकास की कार्य योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, और गरीबी उन्मूलन के साथ आर्थिक विकास के माध्यम से समाज में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना रहा है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सहअस्तित्व वाली एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग करते हुए एक लोकतांत्रिक राजनैतिक ढांचे के तहत की जानी थी। 1960 के दशक में, हरित क्रांति और औद्योगीकरण के युग में, योजनाकारों और नीति-निर्माताओं ने बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित भारतीय औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य निवेश आबंटन, लाइसेंसिंग और अन्य नियामक नियंत्रणों जैसे विविध साधनों के प्रयोग की आवश्यकता का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप, संसद में भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के जरिए यूटीआई अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई।

यूटीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा की गई और इसने इसके विनियामक और प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य किया। इसने 1 फरवरी, 1964 से कार्य करना आरंभ किया। इसका उद्देश्य समाज में बच्चों को बढ़ावा देना और लघु निवेशकों को देश के औद्योगिक विकास में स्टेक अधिप्रापण के रूप में साधन प्रदान कराना था। यूटीआई द्वारा आरंभ की गई पहली स्कीम का नाम यूनिट स्कीम 64 था। वर्ष 1978 में यूटीआई को आरबीआई से अलग कर दिया गया और इसका विनियामक और प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के पास आ गया।

यूटीआई भारतीय पूंजी बाजार में दो दशक से अधिक समय तक निवेश का एकमात्र साधन रहा है, इसके बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, जो एक नियामक निकाय है, की स्थापना के साथ ही इसमें सक्रियता और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को वर्ष 2001 में निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात, 1 फरवरी, 2003 में इस संगठन का - स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्युचुअल फंड (यूटीआईएमएफ) में विभाजन हो गया।

आज, यूटीआई की दोनों शाखाएं, अपने मूल संगठन की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। जनवरी, 2003 के अंत तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट

की स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग की कुल परिसंपत्तियां 29,835 करोड़ रु. की थीं। इसमें मुख्य रूप से यूएस 64 योजना, सुनिश्चित लाभ और कुछ अन्य योजनाओं की परिसंपत्तियां शामिल थीं। यह इकाई, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग है, जो एक प्रशासक के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्य करती है और म्युचुअल फंड विनियमों के दायरे में नहीं आती।

इसकी दूसरी शाखा, यूटीआई म्युचुअल फंड, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित है और यूटीआई एएमसी की प्रदत्त पूंजी में इनमें से प्रत्येक की भागीदारी 18.5% है। यूटीआई म्युचुअल फंड सेबी द्वारा पंजीकृत है और म्युचुअल फंड विनियमों के अंतर्गत कार्य करता है। मूल यूटीआई, जिसमें प्रबंधन के अंतर्गत मार्च, 2000 में 76,000 करोड़ रु. से भी अधिक की परिसंपत्तियां थीं, के द्विभाजन और सेबी के म्युचुअल फंड संबंधी विनियमों के अनुसार यूटीआई म्युचुअल फंड की स्थापना के साथ-साथ निजी क्षेत्र के विभिन्न फंडों के हाल ही में विलय होने से म्युचुअल फंड उद्योग ने समेकन और वृद्धि के मौजूदा दौर में प्रवेश किया है।

यूटीआई भारत का सबसे पुराना एवं विशालतम म्युचुअल फंड है। यूटीआई म्युचुअल फंड विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ करने में अग्रणी रहा है, जैसे जीवन एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा के साथ यूटीआई यूनिट संबद्ध बीमा योजना (यूलिप) (1971 में प्रारंभ)। विगत वर्षों से, ब्रांड यूटीआई जन साधारण हेतु धन उपार्जक की भूमिका निभाता आ रहा है। यूटीआई प्रक्रिया-आधारित एक ऐसा वित्तीय संगठन है, जिसका मुख्य व्यावसायिक सिद्धांत है- निरंतर लाभ और उत्कृष्ट सेवा के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि।

डाक विभाग, यूटीआई के सफर पर स्मारक डाक-टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :-

मूलपाठ	: प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री तथा इंटरनेट पर आधारित
डाक-टिकट/	: कमलेश्वर सिंह
प्रथम दिवस आवरण	
विरूपण	: अलका शर्मा